साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 11-17 सितंबर 2023 वर्ष-9, अंक-22

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

सोलर सिटी सांची का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण, कहा

सांची देश की पहली सोलर सिटीः पीएम का सपना हुआ साकार

सूर्य से बनाएंगे बिजली

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यटन स्थल सांची में सोलर सिटी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सांची नेट जीरो सिटी बनकर पूरे भारत को दिशा दिखाने का काम करेगी। इस दौरान कार्बन उत्सर्जन कम करने, सांची को नेट जीरो बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ अधिकारियों ने एक एमओयू भी साइन किया है। उन्होंने कहा कि सांची ने प्रदेश ही नहीं देश की पहली सोलर सिटी बनकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार किया है। कोयले से बिजली बनाने से पर्यावरण बिगड़ता है। पर्यावरण को बचाने के लिए अब हम सूरज से बिजली बनाना शुरू करेंगे और सोलर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करेंगे। हम कई प्लांट लगा रहे हैं, उनमें से एक ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट बिजली बनाने का काम चल रहा है।

सांची दुनिया को दिखाएगी राह

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि सांची ने सोलर सिटी बनकर वैसे ही दुनिया का पथ प्रदर्शन किया है जैसे कभी भगवान बुद्ध ने किया था। उन्होंने कहा कि सूरज न हो तो सृष्टि न हो, वर्षा भी सूरज के कारण होती है। सूरज ही सनातन है और कुछ लोग सनातन को खत्म करने की बात कह रहे हैं क्या वे सूरज को भी खत्म कर सकते हैं।

5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में लगा प्लांट

सांची में नागौरी पहाड़ी पर 5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लांट लगा है। यहां 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सोलर सिटी सांची में बैटरी चलित ई-रिक्शा एवं बैटरी चलित कचरा वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। सांची में बनाए गए ई-वहीकल चार्जिंग स्टेशन पर चार कमर्शियल चार्जिंग पाइंट तथा तीन ई-रिक्शा चार्जिंग पाइंट बनाए गए हैं। यहां नवीन नवकरणीय ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली की खपत कम करने के लिए 1800 घरों में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि उपकरणों का न्यूनतम दरों में वितरण भी किया जाएगा।

सोलर सिटी के प्रमुख तथ्य

- सोलर सिटी से 14 हजार टन से अधिक कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी
- घरों और सरकारी कामों में व्यय होने वाले विद्युत व्यय में 7.68 करोड़ की वार्षिक बचत होगी
- बिजली बिल में राहत मिलेगी, विश्व के देशों से आने वाले पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी
- रात्रि के समय जगमगाती सड़कों से दुकानें और रहवासी क्षेत्र की गलियां रोशन होने लगीं
- हर-घर सोलर के विचार को अंगीकार किया है। शहर में स्थित दफ्तरों का ऊर्जा आडिट हुआ
- नगरीय आबादी को ऊर्जा की बचत से जुड़े उपायों पर बिन्दुओं पर जागरूक-शिक्षित किया गया

बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जियो टैग मिलने से किसानों की बढ़ी आय

जियो टैग मिलने से बढ़ा चिन्नौर चावल का उत्पादन

- अपने स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर चावल
- इंदौर,भोपाल, जबलपुर,नागपुर और रायपुर में बढ़ी मांग

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में चिन्नौर चावल को जियो टैग मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ी है। इसके साथ ही चावल के उत्पादन के रकबे में भी वृद्धि हुई है।

चिन्नौर चावल को महत्वाकांक्षी योजना एक जिला-एक उत्पाद में शामिल किया गया है। बालाघाट जिले में चिन्नौर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए लालबर्रा और वारासिवनी में दो किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) काम कर रहे हैं। यह समूह लालबर्रा चिन्नौर फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी और चिन्नौर वेली वारासिवनी नाम से काम कर रहे हैं।

75 लाख रहा टर्न ओवर

लालबर्रा कंपनी के अध्यक्ष ईशुपाल चौहान ने बताया कि उनकी कंपनी का कार्यालय ग्राम गर्रा में संचालित किया जा रहा है। शुरुआत में 515 किसान सदस्य इससे जुड़े। इनमें से 400 किसानों ने अपने खेत में चिन्नौर धान लगाया। इस वर्ष सदस्यों की संख्या बढ़कर 700 हो गई और उन्होंने 1500 से 2000 एकड़ में चिन्नौर धान लगाया। पिछले वर्ष एफपीओ का टर्न-ओवर 75 लाख रुपए रहा। किसानों को समझाइश दी गई कि धान उत्पादन में रासायनिक खाद का उपयोग न करते हुए केवल वर्मी कम्पोस्ट जैविक खाद का उपयोग किया जाए।

दूसरे राज्यों में भी हमारे चावल की मांग

चिन्नौर चावल की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए इसकी मांग इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, रायपुर आदि शहरों में हुई। असम के कुछ क्षेत्रों में चिन्नौर चावल की मांग की गई है। कंपनी के पास विदेशों में भी चिन्नौर चावल निर्यात करने के लिए लाइसेंस है। जिले में चावल का उत्पादन बढ़ने पर विदेशों में इसका निर्यात किया जाएगा। बालाघाट रेल्वे स्टेशन में जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल के विक्रय का स्टॉल भी लगाया गया है।

पिछले 4 माह में 99 प्रतिशत पशु बीमारी से मुक्त

स्थिति नियंत्रण में: मप्र में 44 लाख डोज वैक्सीन

लम्पी संक्रमण में पिछले 15 दिनों में आई गिरावट

भोपाल। जागत गांव हमार

गौ-वंश में लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए प्रदेश में प्रतिदिन की मॉनीटरिंग के फलस्वरूप बीमारी का प्रकोप पिछले 15 दिनों में कम होता दिख रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में अब तक 51 लाख 10 हजार 864 पशुओं का एलएसडी रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया जा चुका है। संदिग्ध पशुओं का सतत उपचार जारी है। प्रदेश में एलएसडी वैक्सीन की 44 लाख डोज और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं।

भोपाल में 35 पशु स्वस्थ- प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी गुलशन बामरा ने बताया कि भोपाल जिले में लम्पी बीमारी के प्रथम प्रकरण की सूचना 25 अगस्त 2023 को मिली थी, जिसकी पुष्टि 31 अगस्त को राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला द्वारा की गई। विगत एक माह में भोपाल जिले में 43 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 35 के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। वर्तमान में एलएसडी से पीड़ित 8 पशु उपचाररत हैं।

आसरा में क्वारेंटाइन- संक्रमित पशुओं को पशु आश्रय स्थल आसरा में क्वारेंटाइन कर उपचार किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम द्वारा लम्पी संदिग्ध पशुओं को रखने की अस्थाई व्यवस्था (क्वारेंटाइन सेंटर) नबी बाग के कांजी हाउस में बनाए जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पशुओं के उपचार का कार्य पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा।

भोपाल में 1.24 लाख गौवंश

भोपाल जिले में कुल एक लाख 24 हजार गौवंश हैं। वर्ष 2023-24 में 48 हजार 720 और गत वर्ष 2022-23 में 32 हजार 477 पशुओं का एलएसडी रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किया जा चुका है। वर्तमान में जिले में उपलब्ध 14 लाख 910 वैक्सीन को पशुओं में लगाने का काम जारी है।

प्रदेश के 2 जिले लम्पी प्रभावित

लम्पी स्किन डिजीज का प्रकोप इस वर्ष मई के पहले सप्ताह में बालाघाट जिले से शुरू हुआ था। वर्तमान में प्रदेश के 2 जिले भोपाल और रीवा इससे प्रभावित हैं। प्रदेश में इस रोग से पिछले 4 महीनों में कुल 9 हजार 446 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 9 हजार 323 ठीक हो चुके हैं।

मध्यप्रदेश के महाकोशल-विंध्य और बुंदेलखंड के जिलों में बीते करीब एक महीने से बारिश का क्रम थमा हुआ है। खरीफ सीजन में सूखे की आशंका को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। बिजली की मांग अधिक होने से विभाग ने कृषि फीडरों में दी जाने वाली सप्लाई में कटौती शुरू कर दी है। कटनी में कृषि फीडरों से तीन घंटे की कटौती शुरू हो गई है। बालाघाट, नरसिंहपुर, डिंडोरी, रीवा, शहडोल, मंडला समेत अन्य जिलों में खेतों में दरारें दिखने लगी हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। वहीं रुक-रुक कर हो रही बारिश ने भले ही हल्की राहत दी हो। लेकिन पिछले 15 दिन से अवर्षा के कारण सूखे की आहट आ रही है। जिसके चलते रसोई के सामान के दाम 10 से 20 फीसद बढ़ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पुनः बारिश शुरू हो इसके लिए ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भादौ मास के पहले सोमवार को महारुद्राभिषेक अनुष्ठान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल की महापूजा कर भगवान से उत्तम बारिश की प्रार्थना कर अनुष्ठान का शुभारंभ किया। जानकारों के अनुसार अवर्षा की स्थिति में सृष्टि की अनुकूलता व बारिश का चक्र पुनः प्रारंभ करने की प्रार्थना के लिए भगवान महाकाल का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित ही इससे देव कृपा होगी और सूखे की स्थिति समाप्त होगी। अब हर दिन बारिश हो रही है।

शिव ने की महाकाल की विशेष पूजा

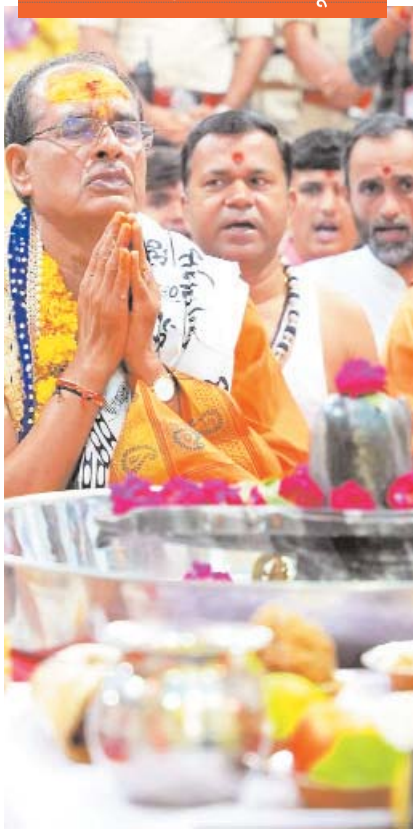

मध्यप्रदेश में अच्छी बारिश के लिए महारुद्राभिषेक

प्रदेश में झमाझम से आहत किसानों को मिली राहत

अगस्त के सूखे के बाद सितंबर में मानसून मेहरबान

जारी रहेगी बारिश, बारिश से फसलों को होगा फायद

महाकोशल-विंध्य-बुंदेलखंड में खरीफ सीजन में सूखे की आशंका

हे महाकाल! सूखे से बचाओ

» मध्यप्रदेश में अभी से आसमान पर दाल, तेल, जीरा घी के दाम

» प्रदेश में हो रही बिजली कटौती ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में अगस्त का सूखा सितंबर पूरा कर रहा है। अगस्त माह में जहां बारिश औसत से बेहद कम हुई तो वहीं सितंबर की शुरुआत से ही मानसून प्रदेश में मेहरबान है और प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस बारिश के कारण न सिर्फ सोयाबीन, धान और मक्का की फसल को फायदा होगा, बल्कि किसानों को भी इससे खासी राहत मिली है। इंदौर शहर में करीब 18 दिन बाद मेघ मेहरबान है। शहर के पूर्वी हिस्से के मुकाबले पश्चिमी हिस्से में ज्यादा बारिश हुई। सितंबर में इस सीजन में पहली बार अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण दिन के पारे में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी इसलिए मैं भगवान महाकाल की शरण में गया तो कल से ही वर्षा शुरू हो गई। किसान चिंता न करें यदि कोई संकट आएगा तो मैं अभी जिंदा हूं। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा के अंदरुनी हिस्से में 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाओं का घेरा बना है। मानसून द्रोणिका लाइन बीकानेर, गुना, मंडला, रायपुर होते कलिंगपट्टनम तक जा रही है। इन दोनों सिस्टम के कारण तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा कुछ हिस्से में बारिश तेज बौछारे भी पड़ेगी। बैतूल सहित जिले के अन्य हिस्सों में तेज बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मानसून के रूठ जाने से खरीफ सीजन की फसलें मुरझाने लगी थीं। वहीं किसानों का कहना है कि यदि कुछ दिन वर्षा नहीं होती तो फसलें सूख जातीं और किसानों को कर्ज के दलदल में फंसना पड़ जाता। अब भले ही देर से बारिश शुरू हुई है लेकिन सोयाबीन और मक्का की फसल से कुछ पैदावार की उम्मीद तो है। छतरपुर में बारिश होने से किसानों की मूंगफली, तिल, पिपरमेंट, उड़द की फसलों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम बना हुआ है, इसलिए अभी बारिश होती रहेगी। बीते दो दिन से शहर सहित बिजावर बड़ामलहरा, लवकुशनगर, हरपालपुर, चंदला आदि क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। नर्मदापुरम जिले में दो दिन से हो रही बारिश ने किसानों को राहत दी है।

तपन से झुलस रहीं फसलें

सिवनी जिले में सूरज की तीखी तपन से फसलें झुलस रही हैं। साढ़े तीन लाख हेक्टेयर रकबे में लगी धान, मक्का, सोयाबीन फसल को बचाने किसान जुटे हुए हैं। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से आक्रोशित किसान धरना दे रहे हैं। शहडोल जिले में धान के खेतों में दरारें दिखने लगी हैं। खेतों में मुरझाए पौधे व उड़ती धूल देख किसानों का मन दुखी है। अब तक 30 प्रतिशत फसल सूख चुकी है।

सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

सीधी जिले में फसलें सूख रही हैं। कुसमी व मझौली अंचल में धान, मक्का, अरहर आदि फसल सूखने लगी है। तिल, उड़द, मूंग आदि में फूल सूखकर झड़ रहे हैं। उमरिया में किसानों ने मानपुर और करकेली क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। करकेली जनपद के कई गांवों में ट्रांसफार्मर जलने से विद्युत आपूर्ति बाधित है।

धान में रोग की भी मार

धान उत्पादक बालाघाट जिले में धान का रकबा 2.58 लाख हेक्टेयर है। बिरसा, खैरलांजी, लांजी, कटंगी क्षेत्र में धान के खेतों में दरारें पड़ रही हैं। अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान का उत्पादन प्रभावित होगा। धान पर तना छेदक व ब्लास्ट नामक रोग भी बढ़ रहा है। अनूपपुर जिले में धान की ग्रोथ रुक गई है। कीट व्याधि से धान का पौधा पीला होकर खराब हो रहा है। रीवा जिले में धान के पौधे में रोग लगना शुरू हो गया है। 35 से 40 प्रतिशत धान की फसल प्रभावित हो चुकी है।

मक्का, सोयाबीन-कोदो-कुटकी प्रभावित

दमोह जिले में 25 हजार 500 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई गई है। बारिश थमने से करीब 10 से 12 प्रतिशत फसल प्रभावित हो चुकी है। यही हालात सतना जिले के हैं, जहां तराई अंचल में धान व सोयाबीन की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। डिंडोरी जिले में धान सहित सोयाबीन, मक्का सहित कोदो कुटकी की फसल भी प्रभावित है। मंडला जिले में धान के पौधों पर कीट लगने का खतरा भी बढ़ गया है। छिंदवाड़ा में खड़ी फसल और सब्जियों को भी नुकसान हो रहा है। चौरई, छिंदवाड़ा ब्लाक में मक्का और मोहखेड़ ब्लाक में उड़द की फसल सूख रही है।

सोयाबीन फसल को बचाने जारी की एडवाजरी

बारिश के आभाव में सुबह-शाम करें सिंचाई

इधर, प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर है। बारिश नहीं होने से ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को कृषि विभाग ने कुछ जरुरी सलाह दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सूखे की स्थिति में जिन कृषकों के पास सिंचाई की व्यवस्था है। वे किसान भूमि में दरार पड़ने के पहले ही फसल में हल्की सिंचाई सुबह या शाम के समय करें। इस समय स्प्रिंकलर से पानी देना अधिक उपयोगी है। इससे पानी की बचत, फसलों में वृद्धि विकास के लिए सुक्ष्म वातावरण, कीट व्याधियों से सुरक्षा में मदद मिलेगी। स्प्रिंकलर भी शाम के समय ही चलाएं। अपने खेत की नियमित निगरानी और खेत में जाकर 3-4 स्थानों के पौधों को हिलाकर देखे कि खेत में किसी इल्ली कीट का प्रकोप हुआ है या नहीं। सोयाबीन की फसल घनी होने पर चक्रमंग का प्रकोप अधिक होने की संभावना होगी। इसके लिए प्रारंम्भिक अवस्था में ही एक सप्ताह के अंदर 2 रिंग दिखाई देने वाली ऐसी मुरझाई लटकी हुई ग्रसित पत्तियों को तने से तोड़कर जला दें या खेत के बाहर करें।

अनुष्ठान का शुभारंभ करने के बाद सीएम शिवराज ने कहा

मध्यप्रदेश में पैदा हो रही सूखे की स्थिति

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। फसलों पर संकट छाया है। महाकाल मंदिर में महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का शुभारंभ और भगवान महाकाल की पूजाअर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है। सब सुखी और निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो इसी भाव से महाकाल महाराज की पूजा की है। वे हम सब पर कृपा की वर्षा करें, अच्छी बरसात हो जाए।

अच्छी बारिश के लिए करें प्रार्थना

सीएम ने कहा कि मैं जनता जर्नादन से अपील करता हूं कि अपने-अपने गांव में, अपने-अपने शहर में जो भी परंपरा हो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना में असर होता है। सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है तो भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। सीएम ने कहा कि अपने-अपने गांव में भगवान की पूजा कर अच्छी वर्षा की कामना करें। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।

बांधों से पानी छोड़ने के निर्देश

उन्होंने कहा कि मैंने अल्प वर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए बैठक की है। उसमें यही निर्देश दिए हैं कि जहां भी बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती हैं उन बांधों से पानी छोड़ा जाए। बारिश नहीं होने के कारण संकट पैदा हुआ है। सावन और भादो में इतनी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती थी

बिजली की मांग भी बढ़ गई

शिवराज ने कहा कि अब बिजली की मांग भी बढ़ गई है। मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया है इसलिए किसानों को भी बिजली कम मिल पा रही है। हमारा प्रयास है कि जहां से भी बिजली मिल सकती है वहां से बिजली लेकर इसकी कमी न आन दें। कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं।

बिजली ना मिलने से फसल बर्बाद होते देख रहे किसान

ग्वालियर-चंबल अंचल से बुंदेल-खंड तक संकट

मानसून सीजन के बावजूद बारिश के लंबे ब्रेक और अब बढ़े तापमान से ग्वालियर-चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक के जिलों में खेतों में खड़ी फसल झुलसने लगी है। जिन किसानों पर ट्यूबवेल से सिंचाई के साधन हैं, वे भी बिजली संकट के कारण अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होते देखने को मजबूर हैं। किसानों को कहना है कि अगर अगले दो-तीन दिन में बारिश नहीं हुई तो फसलें बचनी मुश्किल हैं। शिवपुरी में कृषि विभाग के उपसंचालक यूएस तोमर का कहना है, वर्तमान हालात में मूंगफली और धान, सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

छतरपुर: मूंगफली, मैथा, तिल्ली की फसल सूखने के कगार पर हैं। इस बार 574 एमएम बारिश ही दर्ज हो सकी है, जो औसत बारिश से 25 एमएम कम है।

टीकमगढ़: सोयाबीन व मूंगफली की फसलें सूखने लगी है। जिले में औसत बारिश महज 603 मिमी यानी 60 प्रतिशत रिकार्ड हुई है। शुरुआत में अच्छी बारिश से जो तालाब भर गए थे, वे भी सूखने लगे हैं।

शिवपुरी: अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। मूंग, सोयाबीन में तो फली तक नहीं आई है।

श्योपुर: 21 अगस्त को पहली बार झमाझम वर्षा हुई थी। इसके बाद से वर्षा नहीं हुई है। एक सप्ताह से अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।

मुरैना: 23 अगस्त के बाद से बारिश नहीं हुई। तापमान 37 से 38 डिग्री तक जा पहुंचा है। सबलगढ़, पहाड़गढ़ से लेकर अंबाह-पोरसा क्षेत्र में खड़ी बाजरा की फसल मुरझाने के कगार पर हैं।

भिंड: पिछले पांच से दिन का तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंप कनेक्शन पर महज दो से तीन घंटे ही बिजली मिल पा रही है। तापमान बढ़ने और पर्याप्त बिजली न मिल पाने की वजह से 50 से 60 फीसद धान की फसल प्रभावित है।

दतिया: दतिया सहित सेवढ़ा, इंदरगढ़, भांडेर, बसई, थरेट आदि क्षेत्र के कई गांवों में धान की फसल सूख गई है। मूंगफली, उड़द, मूंग आदि फसल के पत्ते पीले पड़ जाने और माहू इल्ली के प्रकोप से करीब 20 प्रतिशत फसल का नुकसान होने की बात किसान कह रहे हैं।

सोयाबीन की फसल को ज्यादा नुकसान

उज्जैन में मुरझाई फसल किसान हो रहे चिंतित

इधर, उज्जैन जिले में वर्षा की लंबी खेंच, ऊपर से गर्मी का प्रकोप से अब किसान हताश होता दिखाई दे रहा है। पथरीली भूमि व 9560 किस्म की सोयाबीन लगभग 60 प्रतिशत खराब हो गई। देरी वाली सोयाबीन में 5 दिन पानी नहीं आया तो कली ही टूट जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही दल किसानों की फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। वर्षा की लंबी खेंच को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। वर्षा का इंतजार किसान कर रहे हैं। तापमान ज्यादा होने से लोगों को घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा। इससे सोयाबीन की फसल को ज्यादा नुकसान होने की आशंका बन रही है। कृषि विस्तार अधिकारी के अनुसार 30 से 35 डिग्री तापमान पर सोयाबीन में नुकसान नहीं होता है। फसल में पानी की कमी तापमान बढ़ने से भूमि में भी वातावरण की नमी खत्म होती जा रही है। इससे फसल को नुकसान हो रहा है। 9560 किस्म की सोयाबीन जो पथरीली भूमि पर है, उसमें 50 प्रतिशत फली में दाना बना है। अब वह बढ़ नहीं रहा है। सोयाबीन निकालेंगे तो बना दाना हवा में उड़ जाएगा। अन्य किस्म की सोयाबीन के पौधे में कली बन रही है। पानी की कमी के चलते वह कली पौधे से गिर जाएगी।

मालवा-निमाड़ में 55 साल सूखा रहा अगस्त

मालवा-निमाड़ में जैसे-जैसे वर्षा की खेंच लंबी होती जा रही है, वैसे-वैसे किसानों की चिंता अधिक बढ़ रही है। अंचल में मक्का और सोयाबीन की फसलें तेज धूप से जलने लगी हैं। हल्की मिट्टी वाले खेतों में तो हाल और भी खराब हैं। जलस्त्रोत भी दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। खंडवा जिले के एक किसान ने तो आत्महत्या कर ली। इससे उसकी मौत हो गई। ऐसे में किसान संगठन प्रदर्शन कर सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। वहीं देवास जिले के बेहरी के बुजुर्ग किसान भागीरथ पटेल, नाथू सिंह सेठ का कहना है कि 1968 में ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। अगस्त माह के बाद पानी बिल्कुल नहीं गिरा था। नतीजा यह हुआ कि पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ा और लोग भुखमरी से परेशान होकर इधर-उधर पलायन कर गए। मालवा-निमाड़ में कई जिलों में सूखाग्रस्त घोषित करने और राहत पैकेज देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। खंडवा में किसानों ने संयुक्त कृषक संगठन के बैनर तले किसान बचाओ, सरकार जगाओ अधिकार रैली निकाली।

दवा का करें छिड़काव

वर्तमान समय में फसल पर इल्लियों का प्रकोप होने से इल्लियां पत्तों पर चिपकी रहेगी और आसानी से अलग नहीं होगी। किसान भाई सोयाबीन फसल पर पौधा संरक्षण के लिए अनुशंसित कीटनाशक फफूंदनाशक के छिड़?व के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा नेप्सेक स्प्रेयर या टेक्टर चलित स्प्रेयर से 500-600 लीटर है। पावर स्प्रेयर से 125 लीटर है। न्यूनतम का उपयोग करें। सोयाबीन फसल पर पीला मोजेक वायरस के प्रारम्भिक लक्षण दिखते ही तत्काल रोग ग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर निष्कासित करें। अपने खेत पर पीला स्ट्रिकी टेप लगाएं। पीला वायरस रोग को फैलाने वाले वाहक कीट सफेद सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अनुशंसित कीटनाशक एसिटेमीप्रिड का छिड़काव करें। इसके स्थान पर पूर्व मिश्रित कीटनाशक थायोमिथोक्सम+लैम्बडा सायहेलोथ्रिन याबीटा सायफ्लुथ्रिन+ इमिडा क्लोप्रिड का छिड़काव किया जा सकता है। साथ ही सोयाबीन पत्ती खाने वाली तीनों इल्लियों सेमीलूपर तम्बाकू चने की इल्ली या इनमें से कोई एक इल्ली के साथ-साथ रस चूसने वाले कीट सफेद मख्खी एफिड और तना छेदक कीट तना मख्खी के एक साथ नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशक जैसे क्लोर एन्ट्रानिलिप्रोल 9.30 प्रतिशत + लैम्बडा सायहेलोथ्रिन 9.50 प्रतिशत या थायोमि थोक्सम 12.60 प्रतिशत लैम्बडा सायहेलोथ्रिन 9.50 प्रतिशत या बीटासायफ्लुथ्रिन इमिडाक्लोप्रिड 350 मिली लीटर का छिडड़ाव करें।

कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यप्रणाली में होगा बदलाव

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार, भिंड

अब कृषि विज्ञान केंद्र एकल खिड़की ज्ञान संसाधन और क्षमता विकास केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को और अधिक प्रभावी और कार्यशील बनाने की तैयारी की जा रही है जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकेगा। देखा जाए तो किसानों को कृषि एवं कृषि से जुड़ी हुई तकनीकी पहुंचने के लिए इससे बड़ा कृषि प्रसार का कोई दूसरा मॉडल पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देता है।

भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों के खोले जाने की शुरुआत हुए 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में खोला गया था। तब से अब तक कृषि विज्ञान केंद्रों के खोले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पूरे भारतवर्ष में 731 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जिले में किसानों को कृषि में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल पर 1974 में कृषि विज्ञान केंद्रों की शुरुआत की गई थी। तब से अब तक के 50 वर्षों में कृषि विज्ञान केंद्रों ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। लेकिन समय के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यों की ताकत का लोहा आज हर संस्था एवं एजेंसी मान रही हैं। यही कारण है कि आज हर सिस्टम कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर देख रहा है। अब तक कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों, ग्रामीण युवाओं-युवतियों, प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, तकनीकी का मूल्यांकन, प्रचार-प्रसार आदि का कार्य किया जाता रहा है। निश्चित रूप से आगे भी यह कार्य जारी रहेंगे, लेकिन अब फोकस वर्क पर ज्यादा जोर रहेगा। जैव विविधता संरक्षण एवं प्रकृति सकारात्मक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की हैंड होल्डिंग कर उनकी मदद की जाएगी। देश के लगभग 500 कृषि विज्ञान केंद्रों को अपने-अपने जिले में कम से कम पांच-पांच एफपीओ को बढ़ावा देने के साथ उन्हें तकनीकी एवं उनके व्यवसाय में उत्पाद तैयार करने से लेकर बाजार में बेचने तक में हैंड होल्डिंग की तैयारी की जा रही है।

कृषि विज्ञान केंद्रों के मैंडेट में बदलाव के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव पास होते ही कृषि विज्ञान केंद्र एकल खिड़की ज्ञान संसाधन और क्षमता विकास केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। जिसके तहत एकल खिड़की, व्यापार की योजना, डिजिटल कृषि जैसे कई विषय अहम होंगे। एक प्रकार से कहें तो कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में तब्दील हो जाएंगे। जहां पर कृषि, पशुपालन, उद्यानकी, बागवानी आदि के तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही उनसे पैदा होने वाले उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन में सहयोग देने में भूमिका होगी। कृषि व्यवसाय प्रबंधन के साथ ही द्वितीयक कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश की बढ़ती आबादी के साथ

ही जिस प्रकार से किसान की जोत घट रही है उसको देखते हुए सेकेंडरी एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत सरकार का प्रयास है कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर किसानों की आय में अधिक से अधिक इजाफा किया जाए है। एक तरफ कृषि विज्ञान केंद्रों को जिला स्तर पर ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थाओं और तंत्र द्वारा गैर तकनीकी कार्यों में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। आज कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरह अनाज वितरण से लेकर बोर्ड परीक्षाएं, चुनाव कराने, करोना एवं अन्य अनेक राज्य सरकार के कार्यों में लगा दिया जाता है। इस प्रकार की ड्यूटी लग जाने से उनके मूलभूत कार्यों में व्यवधान पैदा होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जिले में किसानों को तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती किसानी का काम हर मौसम, हर माह, दिन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को जिला प्रशासन द्वारा अन्य कार्यों में लगाया जाना जिले के किसानों को तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण में गंभीर व्यवधान पैदा करता है। स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप को कम करने के साथ इन केंद्रों को कृषि एवं उससे जुड़े तकनीकी विषयों के अलावा अन्य अनावश्यक कार्यों से अलग रखने की जरूरत है।

देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र पर बहुत छोटा सा स्टाफ कार्य करता है। एक केंद्र प्रमुख के अलावा, छह वैज्ञानिक तथा अन्य सहायकों सहित कुल 16 वैज्ञानिकों-कर्मचारियों का स्टाफ केंद्र पर कार्य करता है। वस्तु स्थिति के अनुसार ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्रों पर स्टाफ की कमी भी है। ऐसे में जिला प्रशासन या अन्य सरकारी तंत्र कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को अन्य कार्यों से मुक्त रखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का स्टाफ ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। लेकिन एक भी स्टाफ की ड्यूटी अन्य कार्य में लगा दी जाती है तो पूरे केंद्र का कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। पिछले 50 में कृषि विज्ञान केंद्रों ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। वर्ष 1997 में स्टापिंग एवं फंडिंग पैटर्न के बदलाव के साथ ही वर्तमान में केंद्र के वैज्ञानिक एवं कर्मचारी के मौलिक भक्तों में कटौती की भी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। इनमें से कुछ ऐसे भक्ते हैं जो जीवन की मूलभूत जरूरतों तथा अवकाश ग्रहण उपरांत जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन भक्तों में मेडिकल, ग्रेच्युटी, एनपीएस, लीव एनकैशमेंट आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में स्टाफ की कमी को भी पूर्ण करने की जरूरत है। राज्यों व केंद्र सरकार को कृषि विज्ञान केंद्रों को और अधिक सक्षम और सफल बनाने के लिए इन विषयों पर भी विचार करना होगा जिससे कृषि विज्ञान केंद्र और प्रभावी ढंग से किसानों की सेवा में अनवरत रूप से पूरी लगन और निष्ठा से आगे भी कार्य करते रहे।

बच्चों की आत्महत्याओं का हब बनता कोटा

डॉ. विशेष गुप्ता

राजस्थान के कोटा कोचिंग संस्थानों में नवागत छात्र-छात्राओं के बीच आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को मात्र चार घंटे में फिर से दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। एक छात्र ने मॉक टेस्ट में कम अंक आने पर कोचिंग संस्थान की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, वहीं दूसरे छात्र ने अपनी प्रतियोगी परीक्षा के टेस्ट में कम अंक आने पर हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आंकड़े गवाह हैं कि कोटा में इस साल के पिछले 7-8 महीनों में 23 छात्रों, जबकि इसी अगस्त माह में ही सात छात्रों ने आत्महत्या की है। कोटा में ग छात्रों के बीच आत्महत्याओं का इस साल का यह आंकड़ा पिछले एक दशक में सबसे अधिक रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे कोटा कोचिंग हब के साथ-साथ आत्महत्याओं का हब भी बन रहा है। कोटा में आज जिस प्रकार से इन बच्चों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उससे अब कोटा की कोचिंग व्यवस्था पर अनेक सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहले जरा आंकड़ों पर गौर करें, तो पता लगता है कि पिछले दस-ग्यारह सालों में कोटा में 175 से भी अधिक बच्चे आत्महत्या के शिकार हो चुके हैं। कोटा कोचिंग से जुड़े पिछले ग्यारह सालों के आंकड़े भी बताते हैं कि 2011 में छह स्टूडेंट्स ने, 2012 में 11, 2013 में 26, 2014 में 14, 2015 में 18, 2016 में 17 छात्रों, जबकि 2017 में 7, 2018 में 20 विद्यार्थियों, 2019 में 18, 2022 में 15 छात्रों ने खुदकुशी की। कोटा की कोचिंग व्यवस्था में जिस प्रकार इन नाबालिग बच्चों के जीवन में करियर को लेकर एक भावना पनप रही है, उससे भविष्य में इन घटनाओं के और अधिक बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कोटा की कोचिंग से जुड़े आंकड़े साफ करते हैं, कि हर साल दो लाख से भी अधिक टीनेजर्स छात्र कोचिंग के लिए कोटा आते हैं। इन सभी का स्वप्न उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने और उसको उत्तीर्ण करने के बड़े स्वप्नों से जुड़ा हुआ होता है। इस कोचिंग पर अभिभावक हर वर्ष तीन से चार लाख रूपए खर्च करते हैं। कभी-कभी इन छात्रों के अभिभावक कोचिंग की यह फीस बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर भी चुकाते हैं। इसलिए कई बार कोचिंग से जुड़े ये छात्र अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को लेकर भी काफी दवाब में रहते हैं। पिछले दिनों कोटा में कोचिंग कर रहे दर्जन भर छात्रों से संवाद करने पर पाया कि वहां के अध्यापक कोचिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगी छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाकर उन पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरी ओर जो प्रतियोगी छात्र कोचिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कई बार फैकल्टी उन्हें डांट-डपट करती है। साथ ही कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए दूसरों के मुकाबले उनसे बहुत अधिक परिश्रम करने का दबाव भी बनाती हैं। देखने में आया है कि कभी-कभी फैकल्टी ऐसे कमजोर बच्चों का बैच ही अलग कर देती हैं। कई बार कोचिंग संचालक एवं फैकल्टी ऐसे कमजोर बच्चों के अभिभावकों को केन्द्र पर बुलाकर उनके पाल्यों की कमियों को सबके सामने उजागर तो करते ही हैं, साथ में उन्हें वापस ले जाने की धमकी भी देते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि भय का यह मनोविज्ञान इन बच्चों को निराशा से भर देता है। अब वहां खास बात यह है कि अधिकांश अभिभावकों ने आईआईटी/जेईई और मेडिकल की पूर्व परीक्षाओं की तैयारियां के लिए अपने बच्चों को हाई स्कूल के बाद से ही कोटा के कॉलेजों में दाखिला दिला दिया है। आज इंटर और कोचिंग की पढ़ाई दोनों साथ-साथ अध्ययन करने के लक्ष्य उनके सामने हैं। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई और कोचिंग साथ-साथ करने से एक बरस का समय बच जाता है और इन बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी भी अच्छी हो जाती है। इसी दोहरे दबाव के कारण प्रतियोगी छात्र जबर्दस्त द्वंद्व में फंसे रहते हैं। असल बात यह है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग के बावजूद सफलता का प्रतिशत लगभग 25-30 फीसदी के आसपास ही रहता है। इन प्रतियोगी छात्रों की असफलता उन्हें तीव्र अवसाद की ओर ले जाती है। देखने में आ रहा है कि अपने परिवारों से दूर हॉस्टल के कमरों में बंद रहकर 20-20 घंटे कोचिंग करने वाले ये छात्र एक अनजान और बिल्कुल नए माहौल को आत्मसात करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। साथ ही प्रतियोगिता की तीव्र होड़ से उपजने वाली निराशा को कम करने और ढांढस बांधने में अपनों से संवाद का अभाव उन्हें अपने जीवन से हारने को मजबूर करता है। प्रतियोगी परीक्षा की जद्दोजहद और उसमें विफल रहने पर हौसले और सांत्वना देने वालों की कमी नाबालिगों को धीरे-धीरे अवसाद की ओर ले जा रही है।

शहरी बाढ़ से बचाव के लिए कार्रवाई जरूरी

भारत में शहरी बाढ़ अब एक नियमित घटना बन चुकी है। वर्ष 2000 में हैदराबाद, 2005 में मुंबई, 2014 में श्रीनगर, 2021 में चेन्नई और 2022 में बेंगलुरु जैसे शहरों के कई इलाके भारी बारिश से डूब गए। हालिया सर्वे में 94 फीसद शहरी क्षेत्र जलभराव के संकट से जूझ रहे हैं। आजादी से पहले भी शहरी भारत में बाढ़ एक नियमित घटना थी, पर अब इससे क्षति और व्यवधान बढ़ गया है। ज्यादातर शहर किसी-न-किसी नदी के किनारे स्थित हैं। एक आदर्श दुनिया में, ऐसे क्षेत्रों को अछूता छोड़ दिया जाता, पर भारत ने पिछले 30 वर्षों में अपनी 40 फीसदी आर्द्रभूमि खो दी है। 2005 और 2018 के बीच वड़ोदरा ने 30 फीसद आर्द्रभूमि खो दी, जबकि हैदराबाद ने पिछले दशक में अपने 55 फीसदी जलस्रोत खो दिए। चेन्नई ने अनियोजित शहरीकरण के कारण अपनी 90 फीसदी आर्द्रभूमि गंवा दी है। 1997 में दिल्ली में 1,000 जलनिकाय थे, लेकिन अब 700 हैं। कभी 80 किमी वर्ग क्षेत्र में फैली नजफगढ़ झील आज बमुश्किल पांच वर्ग किमी का नाला बन चुकी है। बड़ी झीलें भी विलुप्त हो रही हैं। आलम यह है कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हफनामा देकर कहा कि मायापुरी जैसी कोई झील कभी थी ही नहीं। जबकि इस बात के प्रामाणिक उल्लेख मौजूद हैं कि यह झील 36 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली थी। दिल्ली सरकार ने इसे महज दलदली भूमि कहा है। दिल्ली 2005 से 2023 के बीच चार बार बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। ऐसे ही पैटर्न अन्य शहरों में भी दिख रहे हैं। शहरीकरण के कारण गुवाहाटी ने अपने आधे जलस्रोत खो दिए और इसी अवधि में वहां बाढ़ की पांच बड़ी आपदा आई है। इसके समाधान के लिए कई मोर्चों पर कार्रवाई की जरूरत है।

पहले नदियों सहित तमाम जल निकायों और बाढ़ के जोखिम को समझने के लिए सभी शहरों में अध्ययन होने चाहिए। इसके बाद इसे लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उपायों से जोड़ा जा सकता है। झीलों और नदियों के रखरखाव में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी पर जोर होना चाहिए। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआइएस का उपयोग स्थानीय जल निकायों को टैग करने, अतिक्रमणों पर नजर रखने में मदद करने के लिए किया जा सकता है।

अन्नदाता कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर

किसानों को नहीं हुआ 400 करोड़ के मूंग का भुगतान

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

झमूंग खरीदी के बावजूद भी जिले के कई किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं मिल सका है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मूंग खरीदी के बाद भी भुगतान प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं मूंग के भुगतान को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है। कांग्रेस की ओर से जिले भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भुगतान की मांग की जा रही है। वहीं अब भारतीय किसान संघ ने भुगतान नहीं मिलने पर प्रशासन के खिलाफ पहल करने के लिए चेतावनी दी है। भुगतान को लेकर कृषि विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए राशि जारी की जा रही है। अभी तक किसानों को उनकी खरीदी गई मूंग का लगभग एक करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, वर्तमान में 400 करोड़ का भुगतान लंबित है।

कांग्रेस ने दिया अल्टी-मेटम, करेंगे प्रदर्शन

मूंग के भुगतान को लेकर किसान परेशान हैं तो वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने जिले भर में प्रदर्शन करते हुए मूंग के भुगतान की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष अनोखे लाल राजौरिया ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले किसानों को भुगतान नहीं मिला है, इसको लेकर एसडीएम आशीष पांडे को ज्ञापन सौंपा गया है। राजौरिया का कहना है कि उपज बेचने के 45 दिन बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिल पाया है, जिससे किसान वर्ग आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। तत्काल किसानों का भुगतान किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने दिया ज्ञापन

भारतीय किसान संघ ने मूंग का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। संघ के पांच सदस्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन प्रशासन को दिया गया है। इस संबंध में कृषि उप संचालक कृषि जेआर हेड़ाउ द्वारा प्रतिनिधि मंडल को जानकारी दी गई कि जिले में मूंग उत्पादक किसानों का भुगतान शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। शासन द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी का कुल भुगतान 1 हजार 470 करोड़ किया जाना है।

बीज का तीन साल से नहीं हुआ भुगतान

बीज उत्पादक समितियों के संचालकों ने भुगतान करने की गुहार लगाई है। संचालकों ने बताया कि अन्नपूर्णा सूरज धारा योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति के लिए विभिन्न सीजनों में सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान, गेहूं, चना, मसूर फसलों के प्रमाणित उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्रदान किए थे। जिनका विगत 3 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है अगर 15 दिवस के अंदर हमारा लंबित भुगतान हमारी सहकारी समितियों के खाते में नहीं किया जाता है तो संगठन प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन वह आंदोलन करेगा।

जिला पंचायत कड़कनाथ मुर्गों का उत्पादन कराने की तैयारी में जुटी

अब कड़कनाथ की बढ़ती पूछ परख बढ़ाएगी स्व सहायता समूहों की आय

जबलपुर। जागत गांव हमार

चिकन खाने वालों के लिए कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा सबसे अधिक पसंदीदा माना जाता है। लेकिन, इसका उत्पादन पर्याप्त नहीं होने की वजह से यह सर्वसुलभ नहीं होता। इसी वजह से यह अधिकांश चिकन प्रेमियों की पहुंच से दूर रहता है। इसके दाम भी अन्य मुर्गों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होते हैं। इसी को देखते हुए जिला पंचायत अपने स्व सहायता समूहों के माध्यम से कड़कनाथ मुर्गों का उत्पादन कराने की तैयारी में है। जिले में कुल 10 हजार कड़कनाथ के लालन-पालन के साथ योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए तैयार कार्य योजना को कलेक्टर की ओर से हरी झंडी प्रदान कर दी गई। योजना के अनुसार जिले के 100 महिला स्व सहायता समूहों को कड़कनाथ के उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। इन स्व सहायता समूहों को 100-100 नग कड़कनाथ प्रजाति के चूजे प्रदान किए जाएंगे। इन चूजों की उम्र 28 दिन रहेगी। यानि, चूजे वृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। इनमें से आधे नर और आधे मादा रहेंगे।

जिला पंचायत प्रशासन के अनुसार चयनित स्व सहायता समूहों को चूजों के लिए दड़बा बनाने 17 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। उनके दाने और वैक्सीनेशन के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि यह मदद ऋण के रूप में होगी, जिस पर स्व सहायता समूहों से किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा।

अंडों-मुर्गों का हिसाब-किताब

योजना को अंतिम रूप देने से पहले बकायदा फाइनेंशियल और वेटरनरी के विशेषज्ञों से राय मशविरा किया गया। एक मादा कड़कनाथ साल भर में 80 अंडे देगी। इनमें से कुछ अंडों से चूजे पैदा करने किए जाएंगे। यह संख्या 15 के आस-पास हो सकती है। साल भर बाद पांच से 10 नर कड़कनाथों को बचाकर शेष को 700 से 800 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेच दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक एसएसजी के पास साल भर बाद 500 से अधिक कड़कनाथ की पोल्ट्री होगी।

पोल्ट्री में नर और मादा दोनों होंगे

नर और मादा दोनों होंगे। उपलब्ध मादाओं के अनुरूप कुछ नर कड़कनाथों को आठ महीने बाद फिर बेच दिया जाएगा। समय-समय पर चूजों एवं मुर्गे-मुर्गियों का वैक्सीनेशन होगा। डेढ़ साल की उम्र के बाद मादा कड़कनाथ को भी बेच दिया जाएगा। यही चक्र सफलता पूर्वक चलता रहा तो संबंधित एसएसजी की आर्थिक स्थिति चार से पांच वर्ष में सुदृढ़ हो जाएगी।

- जिले में कड़कनाथ मुर्गों के उत्पादन की योजना तैयार की गई है। जिला प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है। इसके लिए 100 स्व सहायता समूहों का चयन किया गया है। इन समूहों को 100-100 कड़कनाथ प्रदाय किए जाएंगे, जिनमें आधे नर और आधे मादा रहेंगे।

-मनोज सिंह, एसीइओ-जिपं, जबलपुर

करोंद मंडी में किसान पहुंचे, खरीदी से इंकार

प्रदेश की 230 मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी की करोंद मंडी समेत प्रदेश भर की करीब 230 मंडियों में सन्नाटा पसरा है। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश के 25 हजार अनाज व्यापारियों ने खरीदी बंद कर दी है। करोंद मंडी में हजारों किसान सोयाबीन, गेहूं, मूंग, चना, तुअर समेत अन्य फसल बेचने के लिए पहुंचे। लेकिन हड़ताल के चलते व्यापारियों ने खरीदी करने से इंकार कर दिया। मजबूरी में किसान फसल लेकर वापस लौट गए। मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन-तिलहन व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल और भोपाल ग्रेन एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष हरीश कुमार ज्ञानचंदानी ने बताया कि अभी राज्य सरकार मंडी शुल्क 1.5 फीसदी ले रही है, जिसे 1 फीसदी करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। दूसरी ओर, निराश्रित शुल्क समाप्त करने की मांग भी की है। इसका क्या उपयोग हो रहा, यह जानकारी भी व्यापारी वर्ग और किसान को नहीं दी जाती। अब व्यापारी अपनी मांगों के समर्थन में पूरे प्रदेश में विधायक और सांसदों को ज्ञापन देंगे। वहीं, बीजेपी की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान मांगों की तख्तियां लेकर खड़े होंगे।

मुख्य मांगों को किया बंद

मंडी समितियों में कलेक्टर गाइडलाइन से लीज दरों का निर्धारण नहीं रखकर नामिनल दरें रखी जाए। मंडी शुल्क की दर एक प्रतिशत की जाए। निराश्रित शुल्क समाप्त किया जाए। लाइसेंस प्रतिभूति की अनिवार्यता हटाई जाए। कृषक समिति प्रतिभूति बढ़ाने के दबाव पर रोक लगाई जाए।

स्थानीय लोगों को स्वरोजगार भी मिला

खरगोन की धूलकोट पंचायत पीएम आवास बनाने में अव्वल

भोपाल। खरगोन जिले की महाराष्ट्र राज्य से लगी आकांक्षी जनपद पंचायत भगवानपुरा की धूलकोट पंचायत प्रदेश में सबसे अधिक सरकारी आवास बनाने वाली पंचायत बन गई है। जनजातीय बहुल धूलकोट पंचायत में 1667 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के प्रयासों से पीएम आवास का काम आकांक्षी जनपद में मिशन के रूप में किया गया है। इस वजह से धूलकोट पंचायत टॉप-50 रैंकिंग में सबसे ऊपर है। जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण पंचायत क्षेत्र में कच्चे मकान ज्यादा थे। इस वजह से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पात्र हितग्राहियों को बड़ी संख्या में जारी की गई। धूलकोट ने अनोखी डिजाइन के आवास के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

ढाल वाली डिजाइन - सरपंच सालकराम किराड़े बताते हैं कि पक्की छत वाले मकान जनजातीय समुदाय के पूर्वजों की मान्यता अनुसार मान्य नहीं होते हैं। इस वजह से धूलकोट में करीब 70 आवास ढाल वाली डिजाइन में बने हैं। ढाल के साथ छत पर कहीं-कहीं इंगलिश कवेलू और कहीं परम्परागत कवेलू का उपयोग किया गया है। इससे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं।

पीएम आवास में स्वरोजगार

प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित मोर सिंह हबजिया कनोजे बताते हैं कि 3 वर्ष पहले उनका घर बांस से बना कच्चा मकान था। कच्चे मकान के आंधी-बारिश में हमेशा गिरने का डर बना रहता था। पीएम आवास की स्वीकृति मिलने पर आवास बनाने में उन्होंने स्वयं मजदूरी की। पहले वे दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे। अब पक्के मकान में किराना दुकान चला रहे हैं, जिससे अब उन्हें 200 रुपए प्रतिदिन की आय भी हो रही है। धूलकोट में ऐसे कई हितग्राही हैं, जिनके जीवन में बदलाव आया है।

शहर के साथ गांवों का हो रहा विकास...बाणसागर की नहरों से सिंचाई की सुविधा मिलने से किसानों के आए अच्छे दिन

जनसंपर्क मंत्री बोले-विकास में रीवा जिला समृद्धशाली जिले के तौर पर स्थापित होगा

सिलपरा में एक करोड़ के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सिलपरा में जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने एक करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी विकास के कार्य प्राथमिकता से हो रहे हैं। आज रीवा समृद्धशाली जिले के तौर पर स्थापित हो रहा। यहां कम समय में अधिक से कार्यों को कराकर अपनी पहचान बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान शुक्ल ने सिलपरा में 42 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 66.50 लाख के कार्यों का भूमिपूजन किया है। सिलपरा विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सिलपरा सहित आसपास के गांवों में सिलपरी, जोरी आदि समृद्धशाली हुए हैं। बाणसागर की नहरों से सिंचाई की सुविधा मिलने से किसानों की परेशानी नहीं हो रही है। खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। साथ ही सड़कों के बन जाने से यह क्षेत्र उन्नतशील हुआ है।

विकास के पंख लगेंगे और हम उड़ान भरेंगे

मंत्री ने कहा कि यहां की जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। रीवा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के कार्य हो रहे हैं। जिससे अब यहां के लोग रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जा रहे हैं। रीवा में शीघ्र ही हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। कम किराए पर हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन में सफर कर पाएगा। रीवा में हो रही तरक्की से विकास के पंख लगेंगे और हम उड़ान भरेंगे। मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी काम इच्छानुसार होंगे। अब तो आपका विधायक ही पीएचई मंत्री है। पेयजल से संबंधित जो भी कार्य जरूरी हो। वह सब अधिकार के साथ करा सकते हैं। उन्होंने विकास के सहभागी होने का आह्वान किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने नवीन पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, नाली निर्माण, स्कूल में पेवर ब्लॉक और चबूतरा निर्माण के 42 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सामुदायिक पार्क निर्माण, पंचायत भवन में बाउंड्रीवाल एवं पेवर ब्लॉक, नाली निर्माण, नदी में घाट का जीर्णोद्धार व हायर सेकंडरी स्कूल परिसर में सौन्दर्यीकरण के 66.50 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन ने किया।

शिवराज बोले-जहां फसल नुकसान की स्थिति निर्मित होगी, वहां राहत दी जाएगी

किसानों को मिले दस घंटे बिजली और खाद की नहीं होनी चाहिए कमी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य, बिजली, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन,आने वाले त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान पर निर्देश दिए कि बारिश प्रारंभ हुई यह प्रसन्नता की बात है। कई जगह सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है। लेकिन चिंता न करें किसानों का कल्याण मेरी सरकार का मिशन है। सभी जिला अधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखे। जहां भी अल्प वर्षा के कारण नुकसान हुआ। वहां राहत देंगे, फसल बीमा का पैसा देंगे।क्षति का आकलन कर आरबीसी 6(4) के अंतर्गत देंगे। वास्तविकता के आधार पर आकलन कर हम नुकसान होने पर राहत देंगे। यह हमारा धर्म कर्तव्य है।

कृषि के लिए बिजली आपूर्ति करें- बिजली की आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली को लेकर अब स्थिति सामान्य है, अभी एक बार और समीक्षा करेंगे। ऊर्जा विभाग के साथ कलेक्टर कमिश्नर भी आपूर्ति की स्थिति देखे। 10 घंटे कृषि के लिए आपूर्ति सुनिश्चित कराए। एक सिस्टम कार्य करता रहे कि किसानों को। फसलों का नुकसान न हो इसके लिए एडवाइज और समुचित निर्देश देते रहे हैं। जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक जरूर करा लें। बांध में पानी है तो बैठक कर तय करे कि पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं।

जल जीवन मिशन में कहीं कोई कमी न रहे

मुख्यमंत्री ने निर्देश जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा कर लें। सिस्टम बनाए और जांचे कि कहीं कोई कमी न रह जाए। व्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड करें। रिस्टोरेशन का काम सही से हो जाए। सीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुनिश्चित करें कि हितग्राही मूलक योजनाओं का समय पर भुगतान होता रहे। चुनाव की व्यवस्था के कारण कोई दिक्कत ना हो और योजनाएं संचालित होती रही। खाद्य आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करना कलेक्टर की ड्यूटी है। कहीं कोई कमी हो तो समय पर बताएं।

किसानों को खाद उपलब्ध हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, जिलों में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिले में खाद की उपलब्धता का समय पर आंकलन कर, जिले की मांग से राज्य शासन को अवगत कराया जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध हो।

पीएम 14 सितम्बर को आएंगे बीना

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीना आ रहे रहे हैं। पेट्रो केमिकल उत्पाद पर आधारित 50 हजार करोड़ का निवेश प्रदेश में आ रहा है। प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ के कार्यों की शुरुआत करेंगे। इससे प्रदेश में 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है।

प्राकृतिक खेती अपना कर पूरन लाल कमा रहे सालाना 5 लाख

खेती की लागत में आई कमी और खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरा

भोपाल। जागत गांव हमार

छिंदवाड़ा जिले के हर्राई विकासखंड के ग्राम भुमका के प्रगतिशील किसान पूरनलाल इनवाती ने प्राकृतिक खेती को अपना कर अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरनलाल पिछले 6 साल से बिना रसायनों के प्रयोग के प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इससे उनकी लागत में कमी आई है और खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरा है। उनके खेत में पैदा होने वाले अनाज, सब्जी और फलों की मांग बढ़ी है। पूरनलाल बताते हैं कि प्राकृतिक खेती की प्रेरणा भोपाल में प्रशिक्षण के दौरान मिली थी। शुरूआत में प्राकृतिक खेती की शुरूआत आधे एकड़ से शुरू की थी। अब धीरे-धीरे बढ़ कर पूरे 6 एकड़ रकबे में कर रहे है। वे बताते हैं कि उन्हें वर्षभर में 5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। पहले रसायनों, कीटनाशकों के प्रयोग से एक एकड़ में 14 से 15 हजार रुपए का खर्च आता था। अब जीवन अमृत के उपयोग से 80 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। पूरनलाल ने किसान-कल्याण और उद्यानिकी विभाग की नलकूप खनन, स्प्रिंकलर पाइप-लाइन, ड्रिप इरीगेशन, मछली बीज योजना और जंगली जानवरों से बचाव के लिए कॉप गार्ड यंत्र योजना का लाभ भी लिया है। यही नहीं अपने खेत में खेत-तालाब योजना में तालाब का निर्माण भी किया है। प्रगतिशील किसान पूरनलाल ने प्राकृतिक खेती को अपना कर एक एकड़ में केले की खेती, 2 एकड़ में टमाटर एवं अन्य सब्जियां और 2 एकड़ में मक्के की खेती करने के साथ ही फलदार पौधे भी लगाए हैं। उनके काम को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है।

कृषि विकास अधिकारी पर गिरी गाज

भिंड। कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने गोहद के किसानों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए गोहद के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह घुरैया को तत्काल प्रभाव से उर्वरक वितरण कार्य से हटाने और लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए हैं। इसके साथ ही कृषि विकास अधिकारी एके शाक्य व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी डीएस कुशवाह को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। वहीं तहसील कार्यालय लहार में किसान सम्मान निधि की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से किया गया है। तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं मिल पा रहा है। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता रखने वाले किसान मंगलवार को तहसील कार्यालय में लगने वाले शिविर में उपस्थित होकर किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए उपस्थित रहें।

जी20: शिल्प बाजार में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और जनजातीय कला का प्रदर्शन

भोपाल। जी20 शिखर सम्मलेन में विदेशी प्रतिनिधियों और अन्यों के लिए भारत मंडपम के शिल्प बाजार में मध्यप्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प और जनजातीय कलाकृतियों की विस्तृत श्रंखला का प्रदर्शन किया गया। इस शिल्प बाजार के मध्यप्रदेश पेवेलियन में प्रदेश के एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत प्रसिद्ध और लोकप्रिय शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया। पेवेलियन में चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, बाघ और बुटिक प्रिंट, सीधी की दरियां, लौह शिल्प और मेटल की कलाकृतियां, गोंड पेंटिंग्स, जूट से निर्मित कैरी बैग्स, फाइल कवर्स, लेदर बैग्स, बांस चटाई, जरी वर्क इत्यादि के प्रदर्शन और बिक्री की व्यवस्था की गयी थी। डिजिटल भुगतान के लिए पेवेलियन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्ड स्वाइप की सुविधा प्रदान की गई थी। खरीदे गए उत्पादों की पेकिंग इको-फ्रेंडली पेपर बैग में की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से फोरेक्स काउंटर भी शिल्प बाजार में स्थापित किया गया था।

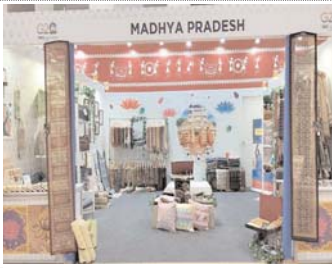

अशोकनगर जिला मुख्यालय से छह किलोमीटर दूर भौरा काछी गांव के रहने वाले भरत सिंह कुशवाह परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए मिसाल बने हुए हैं। 2017-18 में कम्प्यूटर साइंस से बैचलर की डिग्री लेने के बाद भरत सिंह ने कुछ दिनों तक नौकरी की तलाश की। कई प्राइवेट फर्म में इंटरव्यू दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। थक-हार कर परिवार के लोगों के साथ सब्जी की खेती में हाथ बंटाने लगे। इनका परिवार लंबे समय से परंपरागत तरीके से सब्जी की खेती करता आ रहा था। इससे आमदनी इतनी नहीं हो पाती कि पूरे परिवार का खर्च चल सके। इसी दौरान भरत सिंह ने गेंदा फूल की खेती शुरू की, जो सब्जी के मुकाबले बेहतर विकल्प साबित हुआ। एक सीजन में मात्र 20 हजार की लागत से डेढ़ लाख रुपए तक की आमदनी हो रही है।

नौकरी नहीं मिली तो शुरू की 20 हजार की लागत से खेती

गुलजार जिंदगी

सब्जी के मुकाबले बेहतर विकल्प, अन्य का भी बढ़ा रुझान

गेंदा फूल से किसान को एक सीजन में डेढ़ लाख कमाई

अशोकनगर। जागत गांव हमार

2018 की बात है। मैं कम्प्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन के बाद रोजगार की तलाश कर रहा था। कई कंपनियों में साक्षात्कार दिए। दूसरे शहरों में भी जाकर कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से तनाव में रहने लगा था। मेरा पूरा परिवार सब्जी की खेती से होने वाली आमदनी पर निर्भर था। इसी बीच घरवालों ने मेरी शादी अशोकनगर जिले के ही बलनाई गांव में तय कर दी। ससुराल आना-जाना हुआ तो पता चला कि फूलों की खेती से अच्छी आमदनी हो सकती है। मेरे ससुराल वाले फूलों की खेती काफी समय से करते आ रहे हैं। मैंने भी फूलों की खेती करने की इच्छा जताई तो ससुरालवालों ने प्रोत्साहित किया। वे लोग पहले से फूल उगाते आ रहे हैं, इसलिए कई तरह के टिप्स में दिए। ससुरालवालों का सहयोग मिलने के बाद मैंने तय कर लिया कि सब्जी के बजाय अब फूलों की खेती करूंगा। पुराने तरीके से सब्जी की खेती में लागत और आमदनी की खाई बढ़ती जा रही थी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसका विकल्प अपनाना था। मैंने ऐसा ही किया।

पहले साल अच्छी आमदनी हुई तो हर साल खेती का रकबा धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिलहाल मैं दो बीघा खेत में गेंदा फूल की खेती कर रहा हूं। फूल की खेती, निराई-गुड़ाई से लेकर बाजार में बेचने तक का काम खुद ही करता हूं। ससुराल से ही फूलों के पौधों में लगने वाले रोग और उनके निवारण के लिए दवा की जानकारी मिल जाती है। जिले में फूलों की खेती कम होने की वजह से इसकी काफी डिमांड रहती है। गेंदा के फूल की कीमत में हर साल बढ़ रही है। इस साल 60 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक मिलने की उम्मीद है। इस समय 60 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। जबकि त्योहार का समय आते ही 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगा। दीपावली पर 10 दिन तक अच्छा सीजन रहता है। फूलों की खेती से दो महीने तक लगातार आमदनी होती रहती है। इसके बाद उसी जगह पर दूसरी बार फूलों की खेती कर दी जाती है। 2 महीने में दो बीघा खेत में डेढ़ लाख रुपए तक की आय हो जा रही है। जबकि इसमें केवल 20 हजार रुपए की लागत आती है। एक दिन में दो हजार रुपए से ऊपर का फूल बिक जाता है। इसका सीजन 2 से लेकर ढाई महीने तक रहता है।

उज्जैन से मंगवाया था गेंदा पौधा

गेंदा फूल की अच्छी किस्म की पौध नर्सरी में तैयार होती है। भरत कुशवाह भी हर साल उज्जैन की नर्सरी से इसकी पौधे मंगवाते हैं। वहां से अलग-अलग वैरायटी के अलग-अलग दामों के हिसाब से पौधे मिलते हैं। डेढ़ रुपए से लेकर साढ़े तीन रुपए तक में पौधे मिलते हैं।

निराई-गुड़ाई करना जरूरी

पौधे लगाने से पहले खेत को तैयार करते हैं। इसकी दो बार जुताई करने के बाद गोबर का देसी खाद डालते हैं। इसके बाद कतार में पौधे लगाए जाते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 फीट और एक कतार से दूसरे कतार की दूरी भी दो फीट रखी जाती है। इससे पौधे का फैलाव बेहतर तरीके से हो पाता है। साथ ही फूलों को तोड़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। पौधे लगाने के कुछ दिनों के बाद इसकी निराई-गुड़ाई शुरू करनी होती है। पूरे सीजन में दो बार निराई-गुडाई करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा केवल सिंचाई की आवश्यकता होती है।

फफूंद से बचाने की चुनौती

गेंदा के पौधों में केवल फफूंद रोग लगता है। इससे इसके पत्तों पर सफेद रंग की परत जमने लगती है। इसके अलावा तने के अंदर काले रंग का रोग शुरू होता है। हालांकि, यह रोग कभी-कभी आता है। तने काले होने का रोग लगने के बाद दवा का छिड़काव करें।

फूलों के साथ सब्जी की खेती

इस गांव में ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं। यही वजह है कि मंडी में भी भौरा काछी गांव के किसान सबसे अधिक सब्जी लेकर जाते हैं। हालांकि, सब्जी से अधिक फूलों में आमदनी होती है। इसी वजह से अब लोग सब्जी के साथ फूलों की खेती भी करने लगे हैं। 6 साल पहले केवल भरत सिंह ने फूलों की खेती शुरू की थी। इनके बाद अब गांव के दो-तीन और किसान भी फूलों की खेती करने लगे हैं।

जून-जुलाई में लगाएं पौधे

जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती दिनों में गेंदा फूल के पौधे लगाए जाते हैं, जो अगस्त के आखिरी दिनों में फूल देने लगते हैं। इसके बाद ढ़ाई महीने तक इन पौधों से फूल मिलता रहता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी कुछ दिनों तक फूल लगते रहते हैं। शुरुआती दिनों में अधिक फूल टूटते हैं।

अगस्त में भी लगा दिए पौधे

फूलों की डिमांड बाजार में 12 महीने बनी रहती है। इस वजह से वह 2 महीने के अंतर से फूलों की खेती करते रहते हैं। अगस्त के महीने में भी नए पौधे लगा दिए हैं, जो अक्टूबर तक फूल देने लगेंगे। शादी विवाह का सीजन शुरू होते ही फूलों की डिमांड अधिक हो जाती है। इसमें गेंदा के साथ और भी कई प्रकार के फूलों की मांग रहती है। शादी विवाह के समय वरमाला बनाने से लेकर स्टेज सजाने तक के लिए फूलों की जबरदस्त बिक्री होती है।

मिट्टी का पीएच मान 7.0 से 7.6 तक होना चाहिए

ठंड के मौसम में गेंदा की बढ़ोतरी और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है। इस वजह से यह मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। वैसे इसकी खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसम में की जा सकती है। गेंदा की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। गेंदा के लिए मिट्टी का पीएच मान 7.0 से 7.6 के बीच होना चाहिए। गेंदा की फसल को धूप की बहुत जरूरत होती है। छाव में होने पर इसके पौधों में बढ़ोतरी अच्छी होती है लेकिन फूल नहीं लगते है। इसलिए गेंदा की खेती खुले जगह पर ही करनी चाहिए।

दो किस्मों से कर रहे लाखों की कमाई

वैसे तो गेंदा फूल की दर्जनों किस्में होती हैं, लेकिन भरत सिंह अपने खेतों में मात्र दो किस्मों की खेती करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि मात्र इन्हीं दो किस्मों से अच्छी उपज मिल जाती है। साथ ही बाजार में इसकी खपत भी बिना मशक्कत के हो जाती है। यही वजह है कि गेंदा की अन्य किस्मों से दूरी बना रखी है। भरत सिंह गेंदा फूल की जिन दो किस्मों की खेती करते हैं उनमें पहली पूसा संतरा और दूसरी है पूसा वासंती।

3800 कस्टम हायरिंग केन्द्रों का नेटवर्क बनाकर मध्यप्रदेश देश में आगे

खेती में मशीनों के उपयोग को कौशल विकास से जोड़ा

खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ा कर मप्र ने किया क्रांतिकारी काम

» मध्य प्रदेश की पहल अपना रहे हैं कई राज्य

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत 3800 कस्टम हायरिंग केन्द्रों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर खेती में बड़ा बदलाव ला दिया है। किसानों ने 2018-19 से अब तक पिछले पाँच वर्षों में 1 लाख 23 हजार ट्रेक्टर खरीदे हैं, जो प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की बढ़ती पसंद को दर्शाता है। राज्य सरकार कस्टम हायरिंग केन्द्रों को प्रोत्साहित कर रही है, जिन्हें सहकारी समितियां, स्व-सहायता समूह, निजी और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा संचालित किया जाता है, ताकि छोटे और मझौले किसानों को कृषि यंत्रों की सुविधा आसानी से मिल जाए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2012 में कस्टम हायरिंग सेंटर की पहल की थी। इसे वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने अपनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की जरूरत को देखते हुए कृषि मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को बारंबार दोहराया है।

कृषि मेकेनाइजेशन के मॉडल- कस्टम हायरिंग सेंटर इस उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं कि वे 10 किलोमीटर के आस-पास के दायरे में करीब 300 किसानों को सेवाएं दे सके। इन केन्द्रों की सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए केंद्रों की संख्या को सीमित रखा गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3800 किसान कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं। तमिलनाडु, उडीसा, और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी यही मॉडल अपनाने के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

ग्रामीण युवाओं के लिए नौकरी

किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ देने और किराये पर उपलब्ध कृषि मशीनों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश में एक सतत अभियान चल रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर किसानों के ज्ञान और कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। कौशल विकास केंद्र भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, और इंदौर में चल रहे हैं। सभी भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद से संबद्ध हैं। इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए ट्रेक्टर मैकेनिक और कम्बाइन हार्वेस्टर ऑपरेटर कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 4800 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब

मध्य प्रदेश ने कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के संचालक राजीव चौधरी के अनुसार फार्म मेकेनाइजेशन को कौशल विकास से जोड़ने की पहल की गई है। कस्टम हायरिंग सेंटर से छोटे किसानों को किराये पर मशीन मिल जाती है, जिसके लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार 40.00 लाख से लेकर 2.50 करोड़ कीमत वाली नई और आधुनिक कृषि मशीनों के लिए हाई-टेक हब बना रही है। अब तक 85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब बन गए हैं।

कृषि मेकेनाइजेशन से बढ़ा उत्पादन

कृषि मेकेनाइजेशन से उत्पादन, लाभ और उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद मिलती है। गलत धारणा है कि मेकेनाइजेशन से रोजगार के अवसरों में कमी आती है। इसके विपरीत रोजगार की नई संभावनाएं बनती हैं। महंगे कृषि उपकरणों को छोटे किसानों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करने में राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने में मदद कर रही है। यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की प्रति बूंद, अधिक फसल पहल के साथ मेल खाता है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना है। कस्टम हायरिंग सेंटर किराए पर मशीनों को उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिए जा सकें।

शारीरिक श्रम में बचत मशीनों से किसान के शारीरिक श्रम में बचत हो जाती है। मेकेनाइजेशन खेती की लागत को कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। इससे किसान का लाभ बढ़ जाता है। ग्रामीण युवा स्नातक की डिग्री के साथ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें कुल 25 लाख रुपए निवेश की आवश्यकता होती है। उन्हें केवल 5 लाख रुपए की मार्जिन राशि देना होती है। सरकार कुल लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी देती है जो अधिकतम 10 लाख तक होती है। बाकी लागत बैंक ऋण से कवर हो जाती है।

आयुष विभाग की देवारण्य योजना से मिली प्रेरणा

कमलाशंकर ने औषधीय फसलों में नवाचार कर विशिष्ट पहचान बनाई

भोपाल। मध्यप्रदेश में औषधीय खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए आयुष विभाग ने देवारण्य योजना शुरू की है। इससे प्रेरित होकर अनेक किसानों ने अपने खेतों में औषधीय पौधों की पैदावार शुरू की है। नीमच जिले की मनासा तहसील के गांव भाटखेड़ी के प्रगतिशील किसान कमलाशंकर ने इस क्षेत्र में नवाचार कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कमलाशंकर विश्वकर्मा औषधीय फसलों की खेती के साथ जैव-विविधता के क्षेत्र में भी नये प्रयोग करने में सफल हुए हैं। उन्होंने पहले वर्ष में सह-फसल के रूप में अश्वगंधा और शतावरी की औषधीय फसल लगाकर मुनाफा कमाया है। इसके लिये उन्हें 25 हजार रूपये का प्रथम पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसान कमला शंकर बताते हैं कि अब उनके खेत में प्रोफेशनल फोटोग्राफर शूटिंग भी कर रहे हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन में किसान कमलाशंकर ने अपने खेत में बांस के 1100 पौधे लगा रखे हैं। यह सब देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के किसान उनके खेत पहुंचते हैं। उन्होंने खेत में 30 से 40 प्रकार की औषधियों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने का कार्य भी किया है। उनके खेत में कौंच बीज, वराहीकंद, गिलोय, नीली एवं सफेद अपराजिता, घृतकुमारी, कंटकारी, हड़जोड़, हरसिंगार, गुड़हल, नागदौन, अपामार्ग, धतूरा, कनेर, कडुनाय, शिवलिंगी, किंकोडा, विधारा की बेल, छोटी एवं बड़ी दूधी, शतावरी, मूषपर्णी, बहुफली, अतिबला, गोखरू, घमरा, कचनार, पलाश, मेहंदी, बेशर्म बेल/बेहया, खैर, अश्वगंधा, आंवला, बहेड़ा, अरंडी, ईमली, नीम, सीताफल आदि औषधियों के पौधे लगे हुए हैं।

राज्य मंत्री ने सतना जिप के विकास कार्य का किया लोकार्पण

ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पंचायत अपनी आय बढ़ाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके, इसके लिए ग्राम पंचायतों को अपने आय के साधन बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। राज्य मंत्री पटेल सतना जिला पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री ने कहा कि सशक्त पंचायत के लिए जरूरी है कि प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि सजग रहे। उन्होंने जिला पंचायत के करीब 39 लाख रुपए से निर्मित मीटिंग हॉल एवं स्टोर-रूम का लोकार्पण किया। राज्य मंत्री ने 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि-पूजन किया। कॉम्प्लेक्स में 20 दुकानों का निर्माण किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने सतना जिले के देवराज नगर में आज हुए आयुष्मान स्वास्थ्य मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 12 हजार से अधिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य संस्थाओं को इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के मामले में बेहतर किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तरीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेले में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया गया और निःशुल्क दवाई वितरित की गई।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)